International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Vol. 3, Issue 4, April 2016 Impact Factor- 4.866
© Associated Asia Research Foundation (AARF) Publication
Website: www.aarf.asia Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

भारत में जाति की राजनीति का महत्व

डॉ पप्पू राम कोली, व्याख्याता राजनीति वज्ञान ,
राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय , प्रतापगढ़ (राजस्थान) !

सार

जाति एक व्यापक पदानुक्र मत संस्थागत व्यवस्था को संद र्भत करती है जिसके साथ बुनियादी सामाजिक कारक जैसे हैं जन्म, ववाह, भोजन-बंटवारा आदि को पद और स्थिति के पदानुक्रम में व्यवस्थित कया जाता है। ये उपखंड पारंपरिक रूप से व्यवसायों से जुड़े हैं और अन्य के संबंध में सामाजिक संबंध तय करते हैं उच्च और निम्न जातियाँ। जातियों का पारंपरिक श्रेणीबद्ध क्रम भेद पर आधारित था 'प वत्रता' और 'प्रदूषण' के बीच। जब क आदेश का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है हाल के दिनों में, सस्टम ही ज्यादा नहीं बदला है। जाति शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश भाषा से हुई है जाति शब्द का अर्थ जाति है। जाति वशेष में पैदा हुए लोगों की अपनी अलग जाति होती है। यह परिभा षत करता है व्यक्ति के लए सभी सामाजिक, आ र्थक और राजनीतिक संबंध। जाति प्रकृति को निर्धारित करती है, संगठन और राजनीतिक दलों, हित समूहों और सभी राजनीतिक संरचनाओं और उनके काम कर रहा है कार्य करता है। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय राजनीति में जाति की भू मका और यह कैसे बनती है, इसका वश्लेषण करना है संसदीय लोकतंत्र की सच्ची कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बाधा है। जाति एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है जो भारतीय समाज की एक प्रमुख वशेषता है जिसने प्रभा वत कया है सामाजिक आ र्थक और राजनीतिक परिदृश्य में समाज की संरचना। जातिगत मूल्य और जातिगत हित व्यक्तियों की राजनीतिक सोच, जागरूकता और भागीदारी को प्रभा वत करते हैं। राजनीतिक की इस प्र क्रया के कारण जाति का समाजीकरण, जाति चेतना लोगों में जगाती है।

मूल शब्दः राजनीति, जाति, जातिवाद सर्वोपरि

प्रस्तावना

भारत में , एक जाति एक (आमतौर पर अंत र्वाही) सामाजिक समूह है जहां सदस्यता जन्म से तय होती है। जातियों की अक्सर संबं धत राजनीतिक प्राथ मकताएँ होती हैं। मोटे तौर पर, भारतीय जातियों को अगड़ी जातियों , अन्य पछड़े वर्गों , अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों में वभाजित कया गया है , हालां क भारतीय ईसाई और भारतीय मुसलमान भी जातियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत में आरक्षण प्रणाली अनिवार्य रूप से व्यवस्थित रूप से वं चत जाति समूहों को प्रतिनि धत्व प्रदान करने के लए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कार्य करती है।

भारतीय राजनीति में जातिवाद

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप वक सत हुआ। अतः यह संभावना व्यक्त की जाने लगी क देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्था पत होने पर भारत से जातिवाद समाप्त हो जायेगा ले कन ऐसा नहीं हुआ बल्कि जातिवाद ने न केवल समाज में बल्कि राजनीति में भी प्रवेश करके उग्र रूप धारण कर लया है। भारत में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आ र्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धा र्मक प्रवृतियों को ही प्रभा वत कया है, बल्कि राजनीति को भी पूर्ण रूप से प्रभा वत कया है। भारत की राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भू मका निभाई है। केन्द्र ही नहीं राज्यस्तरीय राजनीति भी जातिवाद से प्रभा वत है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लए बहुत ही खतरनाक है, क्यों क इसके कारण राष्ट्रीय एकता एवं वकास मार्ग अवरुद्ध हो रहा है।

राजनीति में जातिवाद सर्वोपरि

भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में जातिवाद सर्वोपरि है, जातिवाद कसी न कसी प्रकार हमारी राजनीति को प्रभा वत करती है, सं वधान निर्माण के समय से ही इनमें कुछ सुधार कये जा रहे हैं, कभी कन्हीं राजनेताओं के द्वारा तो कभी सुधार प्रस्ताव के द्वारा जातिवाद नामक मान सकता को सुधारने का प्रयास कया जाता रहा है। इसका गवाह इतिहास स्वयं है, आज राजनीति में या मनुष्य के जीवन को यदि सबसे ज्यादा प्रभा वत कुछ करता है, तो वह है " जातिवाद " इसकी जड़े प्राचीनकाल से ही इस कदर भारतीय राजनीति में जमी हुई है क इसे निकाल फेंकने का प्रयास भर मानव मात्र कर पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में अपनी जड़ों को जमाये हुए हैं, जो वर्तमान राजनीति में एक भयंकर बीमारी प्रतीत होता है। हमारे समाज में एक बड़ी ही व्यापक और मुख्य भू मका अति पछड़ों तथा द लतों की है, द लतों का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही वशेष भू मकाएँ रही हैं, ये समाज के ऐसे वर्ग है, जो अपना एक अलग महत्व रखते हैं, अब प्रश्न ये है क ये द लत आये कहाँ से

इसकी जड़ में जातिवाद है। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण वश्व में जातिप्रथा कसी न कसी रूप में व्याप्त है, जो एक गंभीर सामाजिक कुरीति है।

वर्ण व्यवस्था

वैदिक काल में वर्ग - वभाजन कया जाता था , जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। यह जातिगत न होकर गुण एवं कर्म पर आधारित था। समाज चार वर्गों में वभाजित था। ब्राह्मण धा र्मक तथा वेदों से जुड़े कार्य करते थे। क्षत्रिय को देश की रक्षा तथा प्रशासन से जुड़े कार्य का दायित्व था। वैश्य कृ ष और व्यापार से जुड़े कार्य करते थे, तथा शूद्र को इन तीनों वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। वर्ण व्यवस्था और जाति - व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है क वर्ण का निर्धारण व्यवसाय से होता था, जब क जाति का निश्चय जन्म से होता था। इस प्रकार जाति प्रथा भ्रष्ट सद्ध होती गई। प्रो. रुडोल्फ के अनुसार भारत राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है, जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गयी है क इसके जरिए भारतीय को लोकतांत्रिक राजनीति की प्र क्रया से जोड़ा जा सकता है। प्रो ० रजनी कोठारी अपनी पुस्तक "कास्ट इन इण्डियन पॉ लटिक्स" में भारतीय राजनीति में जाति की भू मका का वस्तृत वश्लेषण कया है। उनका मत है क बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है क क्या भारत में जातिप्रथा खत्म हो रही है? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है क मानो जाति और राजनीति परस्पर वरोधी संस्थाएँ हैं।

जाति और राजनीति में आपसी संबंध

भारत में जाति और राजनीति में आपसी संबंध को समझने के लए चार प्रमुख बिन्दुओं को समझना आवश्यक है:

भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन ही जाति के आधार पर हुआ है। राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अ भव्यक्ति मात्र है, इस लए सामाजिक व्यवस्था राजनीति का स्वरूप निर्धारित करती है।

लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक प्र क्रया जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है, ता क उनका सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी अ धक मजबूत बना सके।

भारतीय राजनीति सदैव ' जाति ' के इर्द - गर्द घूमती है, यदि कसी व्यक्ति वशेष को राजनीति में सफलता चाहिए तो वह कसी संगठित जाति का सहारा लेता है।

वर्तमान में जाति वशेष का संगठन ही ज्यादातर राजनीति में भाग ले रही है। अतः स्पष्ट है क वर्तमान में जाति का वशेष महत्व राजनीति में है। समाज के व भन्न वर्गों तथा जातियों का समर्थन पाने के लए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता उन सब संस्थानों के खलाफ थे।

भारतीय राजनीति में जातिवाद जिनकी प्रवृत्ति भारतीय जनता को वभाजित करने की थी। लोगों द्वारा वशाल जनसभाओं और सत्याग्रह संघर्षो में सामूहिक रूप से भाग लेने से जाति चेतना बिल्कुल कमजोर गयी थी, जो लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता और समानता के नाम पर अंग्रेजी शासन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे जाति व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते थे। इस प्रकार आरंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वस्तुतः संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन जातिगत वशेषा धकारों का वरोधी रहा। कांग्रेस ने जाति, लंग और धर्म के भेदभाव के बिना मानव जाति के वकास के लए समान नागरिक अ धकारों तथा समान स्वतंत्रता के लए हमेशा संघर्ष कया।

बाबा साहब का योगदान

द लतों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जो स्वयं एक द लत थे, उन्होंने अपना सारा जीवन जातिगत जुल्म के खलाफ लड़ने में लगा दिया। उन्होंने अ खल भारतीय द लत वर्ग संघ **(All Indian Depressed Classess Federation)** की स्थापना इसी उद्देश्य से की ता क द लतों में जागृति की भावना को वकास हो अनुसू चत जनजातियों के कई अन्य नेताओं ने अ खल भारतीय द लत वर्ग परिषद् (स मति) की स्थापना की द क्षण भारत में गैर ब्राह्मणों ने बीसवीं सदी के तीसरे दशक के दौरान ब्राह्मणों द्वारा अपने उपर लादी गई निर्योग्यताओं के खलाफ संघर्ष करने के लए "आत्मसम्मान" आंदोलन चलाया। सारे भारत में मंदिर प्रवेश पर रोक तथा इसी तरह के अन्य प्रतिबंधों के वरोध में द लत जातियों ने अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाये। डा॰ बी आर अम्बेडकर अपनी मृत्यु के बाद द लतों के लए एक आदर्श के रूप में उभरे हैं द लतों को इससे काफी लाभ मला है। वे इनके लए एक उदाहरण और प्रेरणा दोनों ही रहे हैं। वे उच्च कोटी के बु द्धजीवी थे, जिन्होंने उच्च जातियों द्वारा बनाये गये धेरे को तोड़ा तथा उनकी मृत्यु के कई दशकों के बाद भी आम्बेडकरवादी उनके सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। अम्बेडकर के व्यक्तित्व ने पूरे देश में द लतों को एक सूत्र में बाँध रखा है।

भारत में सामाजिक सुधार

परंपरागत भारतीय समाज में जाति - व्यवस्था की संपूर्ण संरचना इस प्रकार थी जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी, ले कन आज सामाजिक व्यवस्था की रूप - रेखा राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित होती हैं। आधुनिक मूल्यों के उदय के साथ ही धा र्मक वश्वास स्वयं ही लौ कक जीवन

से दूर हट रहे हैं। व्यक्तियों को सं वधान द्वारा समानता का अ धकार दिया गया है। अतः व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण आज जातिगत स्थितियों से न होकर उसकी योग्यता और कुशलता के आधार पर हो रहा है। जाति व्यवस्था की संरचना स्तरण में जिन व्यक्तियों को अस्पृश्य द लत अथवा अंत्यज मानकर समस्य अ धकारों से वं चत कर दिया गया था। उनकी स्थिति में आज काफी परिवर्तन हुआ है।

महात्मा गांधी और अंबेडकर के प्रयत्नों से इन व्यक्तियों को समान अ धकार ही नहीं दिये गये, बल्कि सभी सरकारी नौकरियों व राजनीतिक संस्थाओं में उनके लए स्थान भी आर क्षत कर दिये गए हैं, जिससे उनकी सामाजिक, आ थक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके। समकालीन भारत में अन्तर्जातीय ववाहों की संख्या में निरंतर वृ द्ध हो रही है। वधवा ववाह को अ धक से अ धक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कानूनों द्वारा ऐसे ववाहों को मान्यता दे दी गई है।

पारंपरिक जाति - व्यवस्था में प्रत्येक जाति अपने से निम्न जाति के लोगों से छुआ छूत का भेदभाव रखते थे तथा उनके द्वारा स्पर्श कये गए भोजन को ग्रहण नहीं करती थी। जब क वर्तमान में जातिगत भेद भाव का यह आधार लगभग समाप्त ही हो गया है। आजकल शहरों में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ फैक्ट्रियों और अन्य कार्य स्थलों में काम करते हैं और अवकाश के समय सब साथ बैठकर भोजन करते हैं। होटल, जलपानगृहों तथा ववाह या अनेकों उत्सव में भी सभी जातियों के व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करते हैं जिसे कसी अज्ञात जाति के व्यक्ति द्वारा बनाये गए हों जिनका स्पर्श करना भी जाति व्यवस्था द्वारा कभी वर्जित था।

जाति व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह कहना था क वह अपनी जाति के सदस्यों से ही अ धकतम संपर्क बढ़ाए उच्च जातियों की श्रेष्ठता में वश्वास रखे और निम्न जातियों से दूरी बनाए रखे। आज बहुत से उच्च जातियाँ अपने स्वार्थों को पूरा करने के लए उन सभी व्यक्तियों से संपर्क स्था पत करती है।

जाति व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जाति का व्यवसाय जन्मजात से ही निश्चित होता था। वर्तमान समय में काम के आधार पर जाति का आधार लगभग समाप्त हो चुका है। शहरों में सभी जातियों के व्यक्ति अपने - अपने अलग व्यवसाय में लगे होते हैं, अब व्यवसायिक जीवन की गतिशीलता ने सभी जातियों को समान जी वकोपार्जन का अवसर प्रदान कया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कुलदीप संह महोदय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय में लखा है: भारतीय सं वधान ने जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और इसने व ध के समक्ष लोगों में समता का आश्वासन दिया है। सं वधान के अनुछेद **15 (2)** और **16 (2)** के अधीन जाति

के प्रति निर्देश केवल इसे समाप्त करने के लए ही है।इसी निर्णय में आगे लखा गया है की अब जाति व्यवस्था, जिसे सं वधान के रचयिताओं ने समाप्त कर दिया है, व भन्न रूपों में अपना धृ णत सर उठाने का प्रयत्न कर ही है।

जाति और चुनाव समीकरण

भारत में **1952** में पहली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब उस समय की राजनीति में द लतों की कोई खास भागीदारी नहीं थी। राजनीति में द लत और आदिवा सयों की वोट की ताकत का महत्व का एहसास नहीं था भारत में चुनाव अ भयान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा होता है, उस क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है, ता क संबं धत प्रत्याशी की जाति के मतदाओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त कया जा सके।

सभी राजनीतिक दलों द्वारा यह माना जाता है, क राज्यस्तरीय मंत्रिमण्डलों में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री अवश्य होना चाहिए। केवल प्रांतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायती स्तर भी यह भावना काम करती है। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत हैं।

कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जहाँ पर राजनीति जातिवाद से प्रभा वत नहीं हो रही केरल, त मलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि सभी राज्यों की राजनीति पर जातिवाद स्पष्ट रूप से हावी है। जाति के आधार पर भेदभाव भारत में स्वतंत्रता से पहले भी वद्यमान था, ले कन स्वतंत्रता के बाद प्रजातंत्र की स्थापना होने से समझा गया क जातिगत भेद समाप्त हो जायेगा, ले कन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक संस्थाएँ भी जातिगत से प्रभा वत हुए बिना नहीं रह सकी। फलस्वरूप जाति का भारत में राजनीतिकरण हो गया।

जातिवाद देश के वकास में बाधक

जाति का राजनीतिकरण भारत के आधुनिकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक सद्ध हो रहा है, क्यों क जाति को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं समरसता का निर्माण करने हेतु आधार नहीं बनाया जा सकता। वैसे तो सं वधान द्वारा अस्पृश्यता को लेकर अनेकों कानून बनाए गए, परन्तु जाति - वहीन समाज की स्थापना सं वधान की अंतरात्मा नहीं बन पाई। अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई परन्तु जाति व्यवस्था स्वयं बनी रही।

अनुच्छेद **17** का अंबेडकर द्वारा कया गया प्रारूप यह था क रैंक, जन्म, व्यक्ति, परिवार, धर्म या धा र्मक रूढि और रीति - रिवाज से उत्पन्न कसी वशेषा धकार या नियोग्यता को समाप्त कया जाता

है, परंतु इसे न तो प्रारूप स मति ने स्वीकार कया और न ही सं वधान सभा ने स्वीकार कया। बिना चर्तुवर्ण या जाति का नाम लए अंबेडकर ने इन पर आधारित वशेषा धकारों या निर्योग्यताओं को समाप्त करने का प्रयास कया था, यदि उसे स्वीकार कया गया होता तो वह सामाजिक समता तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा के ज्यादा करीब होता।

वर्तमान सं वधान का अनुच्छेद **-17** डॉ. के एम मुंशी के प्रारूप पर आधारित है। इसके पूर्व **1930** के दशक में मंदिर प्रवेश के लए हरिजनों को प्रदान की जाने वाली व्यवस्था पर प्रति क्रया व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने स्पष्ट कया था, क यदि हिन्दू धर्म उनका धर्म होना है, तो उसे सामाजिक एकता का धर्म होना होगा। मात्र हिन्दू संहिता का संशोधन कर मंदिरों में प्रवेश दिलाना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है क जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के जनक चर्तुवर्ण के सद्धांत को समाप्त कया जाय।

डॉ आर सी मजुमदार ने अपनी पुस्तक **"**स्ट्रगल फॉर फ्रीडम**"** में स्पष्ट लखा है क इसका मात्र संतोषजनक उत्तर यह हो सकता था क तीन हजार वर्षों से चली आ रही पुरानी जातिवादी व्यवस्था एक दिन में समाप्त नहीं सकती और इसके लए धीरे-धीरे प्रयास जारी रखना होगा। परंतु महात्मा गांधी सहित कसी हिन्दू नेता ने यह स्पष्ट रूप से जाति व्यवस्था के वरुद्ध वचार व्यक्त नहीं कया।

प्रत्येक राज्य में द लत अल्पसंख्यक हैं, जो व भन्न जातियों के साथ म श्रत जनसंख्या वाले समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। इसका अर्थ यह है क चुनाव के समय वे उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं, संघ के सभी राज्यों में और हर राज्य के प्रत्येक जिले में **10** प्रतिशत से **20** प्रतिशत के बीच उनका वोट है। इस लए राजनीतिक दलों को अ धकांश लोकसभा और वधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में द लत हितों का ध्यान रखना पड़ता है। द लत मतदाता लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्णय में असरदार भू मका निभाते हैं।

पूरे देश में द लतों को तकरीबन एक ही तरह के दमन का सामना करना पड़ा है तथा उनके साथ भेदभाव कया जाता रहा है। इस प्रकार के समान अनुभव के कारण राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर द लतों की एकजुट होने में मदद मली है। पूरे देश में द लतों के साथ एक ही तरह का व्यवहार कया जाता है। इसका कारण यह है क जाति व्यवस्था पूरे भारत में एक ही तरह से कार्य करती है। त मलनाडु के गांवों की तरह उत्तर प्रदेश के गांवों में भी द लतों को सबसे निम्न कोटि का कार्य दिया जाता है, उन्हें उच्च जाति की बस्तियों से दूर बसने पर मजबूर कया जाता है। उन्हें दू षत जन स्रोतों से ही पानी लेने की अनुमति दी जाती है, और मंदिर में प्रवेश पर रोका जाता है। इस लए वे गांवों जिलों और राज्यों के बीच क्षैतिज एकजूटता और जुड़ाव का वकास कर सकते हैं जातिप्रथा के कारण समाज टुकड़ों में बंट गया,

व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव बढ़ता गया, अहंकार और द्वेष के फलस्वरूप भारतवासी कभी एक नहीं हो सके, फलस्वरूप भारतवा सयों को हमेशा वदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा।

अति पछड़े और द लत एक छोटी संख्या वाली जातियाँ हैं और इनका ठिकाना गाँव शहर में जहाँ - तहाँ फैला हुआ है, और इनकी इस अवस्था के कारण लोकतांत्रिक राजनीति में या चुनावों में इनका कोई खास योगदान नहीं रहता। ये ज्यादा समय अपनी जी वकोपार्जन की समस्याओं को सुलझाने में लगे होने के कारण ज्यादा समय राजनीतिक चुनावों को नहीं दे पाते। शक्षा के अभाव के कारण भी इनमें कोई बड़ा राजनीतिक नेतृत्व वक सत नहीं हो पाता।

वर्तमान में धीरे-धीरे सरकारी योजनाओं के लाभ लेते हुए अब इनमें चेतना जागृत हो रही है, इनका रूझान अब शक्षा त वकास की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे राजनीति में भी इनकी भागीदारी बढ़ रही है। ये धीरे-धीरे संगठित होकर एक बड़े वोट बैंक में तब्दील हो रही है। समय के साथ-साथ अब पछड़ी जातियों को वधानसभा चुनाव में टिकट भी दिये जा रहे हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज जातिगत भेद-भाव जैसे भयानक बीमारियों से जकड़ा हुआ है, इसका गंभीर बीमारी का निदान खोज पाना कठिन मालुम पड़ता है। यह केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच खाई पैदा नहीं कर रही बल्कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्र सद्ध समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास का मत है क "परंपरावादी जाति व्यवस्था" ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभा वत कया है, क ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूलरूप में कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः देश में फैला हुआ जातिवाद समाज और राजनीति के लए बाधक सद्ध प्रतीत होती है। यह दुर्भाग्य की बात है क भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था इस प्रकार की स्थितियों का निर्धारण करती रही है जिससे गरीब हमेशा द लत अ श क्षत सामंतवादी उपनिवेश बने रहे। जात-पात बहुल हमारे इस समाज से यह अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है क समाज में व्याप्त यह भयंकर बीमारी अचानक से चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाय इस सच्चाई को कोई कतना भी नकारे ले कन आज भी भारतीय जनतंत्र की राजनीति के केन्द्र में नागरिक न होकर जाति ही है।

सन्दर्भ सूची

1. दत्ता, ए.आर. (संस्करण 2013)। भारत में राजनीति: मुद्दे, संस्थाएं, प्र क्रयाएं। अरुण प्रकाशन, पानबाजार, गुवाहाटी-1

2. एट्ज़ियोनी, ए., (1965) "पॉ लटिकल यूनि फकेशन: ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ़ लीडर्स एंड फोर्सेस", न्यूयॉर्क: होल्ट, राइनहार्ट और वंस्टन, इंक।

3. कोठारी, रजनी।, (1989) "राजनीति और लोग; एक मानवीय भारत की तलाश में", Vol.1, अजंता, नई दिल्ली।

4. कोठारी, रजनी, (1970) "पॉ लटिक्स इन इं डया", बोस्टन, लटिल ब्राउन

5. जौहरी, जे.सी., (1973) "कास्ट पॉ लटिकाइजेशन इन इं डया" इं डयन पॉ लटिकल साइंस रिव्यू, 7 (2)

6. कोठारी, रजनी, (1970) "कास्ट इन इं डयन पॉ लटिक्स" ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।

7. जोन्स, डब्ल्यू.एच., (1967) "द गवर्नमेंट एंड पॉ लटिक्स ऑफ इं डया", ह चंसन यूनिव र्सटी लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क।

8. रूडोल्फ, एल.आई., और रूडोल्फ, एस.एच. (1967)। परंपरा की आधुनिकता: भारत में राजनीतिक वकास। शकागो: शकागो वश्व वद्यालय प्रेस।

9. जौहरी, जे.सी. (2000) "भारतीय राजनीतिक प्रणाली", अनमोल प्रकाशन, तीसरा संशो धत संस्करण, नई दिल्ली

10. हसन, ज़ोया, (संपा.2002) "पार्टीज़ एंड पार्टी पॉ लटिक्स इन इं डया", ऑक्सफोर्ड यूनिव र्सटी प्रेस, नई दिल्ली

11. ब्रास, आर. पॉल, (1994) "द पॉ लटिक्स ऑफ इं डया संस इं डपेंडेंस", कैम्ब्रिज यूनिव र्सटी प्रेस

12. कोठारी, रजनी।, (1961) "फॉर्म एंड सब्सटेंस इन इं डयन पॉ लटिक्स", द इकोनॉ मक वीकली, जून, 3।